

राजपन्न, हिमाचल प्रदेश

(मसाधारण)

हिमाचल प्रवेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 मई, 1987/26 वैशाख, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

ग्रधिसूचना

शिमला-4, 3 अप्रैल, 1987

ेसंख्या 1-20/87-वि0स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के प्रन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1987 (1987 का विधेयक संख्यांक 6) जो दिनांक 3 ग्रप्रैल, 1987 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

विश्वेश्वर वर्मा, सचित्

1987 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1987

(विधान सभा में यथा पुर:स्थापित)

वित्तीय वर्ष 1984-85 में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, कितपय मेवाग्रों पर, उन सेवाग्रों के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से ग्रधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कितपय रकम के विनियोजन के प्राधिकरण के लिए उपवन्ध करने के लिए विश्वेयक ।

भारत गणराज्य के ग्रड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह ग्रधिनियमित हो :—

- 1. इस म्रधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) म्रधिनियम, संक्षिप्त नाम 1987 है।
- 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 32,93,23,314 रूपये (बत्तीस करोड़, तिरानवें लाख, तेईस हज़्रर, तीन सी चौदह रुपये) है, वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधिमें से 1984-85 वर्ष के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 32,93,23,314 रुपये की धातिरक्त राशि का प्राधिकरण।

3. इस ग्रिधिनियम के ग्रिधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त ग्रीर उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित ग्रुनुसूची में ग्रिभिव्यक्त, सेवाग्रों ग्रीर प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी ।

विनियोग

ग्रनुसूची

(धाराएं 2 ग्रौर 3 देखें)

1	2	}	तिम्नलिखित राणियों से म्रनधिक .			
मांग संख्या	सेवाएं ग्रीर प्रयोजन		विधान सभा द्वारा	संचित निधि	जोड़	
			दत्तमत	पर प्रभारित	1	
2	राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	6, 32, 281		6,32,281	
5	भू-राजस्व	(पूंजी)	1,40,400	_	1,40,400	
6	श्रोबकारी तथा कराधान	(रोजस्व)	91,274		91,274	
8	शिक्षा, कलातथा संस्कृति एवं	(राजस्व)	2,29,07,647		2,29,07,647	
	वैज्ञानिक श्रनुसंधान	(पूंजी)	21,52,069		21,52,069	
10	लोक निर्माण	(रोजस्व)	12,72,84,093		12,72,84,093	
12	लघु सिचाई	(राजस्व)	1,84,05,271		1,84,05,271	
	•	(पूंजी)	10,12,779		10,12,779	
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(पूँजी)	96,543		96,543	
16	वन	(रोजस्व)	35,57,832		35,57 332	
		(पूंजी)	5			
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	1,21,44,608		1,21,44,608	
		(पूंजी)	1,37,66,652		1,37,66,652	
20	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल स्रापूर्ति	(पूंजी)	3,99,030		3,99,030	
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(पूंजी)	5,48,031		5,48,031	
28	पर्यटन	(पूँजी)	3,498		3,498	
29	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	1,60,936		1,60,936	
30	भावास	(राजस्व)	10,57,823		10,57,823	
32	ग्रन्य प्रशासनिक सेवाएं	(पूंजी)	38,32,553		38,32,55	
33	वित्त	(राजस्व)	1,36,21,257		1,36,21,25	
		(पूंजी)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9,57,46,834	9,57,46,83	
35	जन जातीय विकास	(राजस्व)	1,17,61,898		1,17,61,89	

23,35,76,480

9,57,46,834 32,93,23,314

जोड़

उद्देश्यों ग्रौर कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के माथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए, अनुदान और विनियोजन से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपयन्ध करने के लिए प्रःस्थापित है।

शिमला : श्रप्रेल 3, 1987. वीरभद्र सिंह, मख्य मन्त्री।

भारत के सविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल सं0 फिन-ए-सी-(2) 1/86 II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1987 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुक्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने श्रीर उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Sankhya 3) Vidheyak, 1987 (1987 ka Vidheyak Sankhyank 6) as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

Bill No. 6 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1987

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1984-85 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

- 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1987.
- Authorisation of a further sum of Rs. 32,93,23,314 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the year 1984-85.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 32,93,23,314 (thirty-two crores, ninety-three lakhs, twenty-three thousand, three hundred and fourteen rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 1984-85 in excess of the amount authorised or granted for these services and for that year.

Appropriation. 3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 1984-85.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3			
kīnmh	nor.	Sums not exceeding			
Number of Services and purposes Demand			Voted by the Legisla- tive Assem- bly	Charged on the Consoli- dated Fund	Total
2	Governor and Council of Minister	rs (Revenue)	6,32,281	_	6,32,281
5	Land Revenue	(Capital)	1,40,400	_	1,40,400
6	Excise and Taxation	(Revenue)	91,274	1	91,27
8	Education, Art and Cultural Affai and Scientific Research.	irs (Revenue) (Capital)	2,29,07,647 21,52,069	=	2,29,07,64° 21,52,06°
10	Public Works	(Revenue)	12,72,84,093	_	12,72,84,09
12	Minor Irrigation	(Revenue) (Capital)	1,84,05,271 10,12,779	=	1,84,05,27 10,12,77
13	Soil and Water Conservation	(Capital)	96,543		96,54
16	Forest	(Revenue) (Capital)	35,57,832 5	=	35,57,83
17	Roads and Bridges	(Revenue) (Capital)	1,21,44,608 1,37,66,652	=	1,21,44,608 1,37,66,652
20	Public Health, Sanitation and Wate Supply.	3,99,030	_	3,99,030	
26	Stationery and Printing	(Capital)	5,48,031		5,48,031
28	Tourism	(Capital)	3,498		3,498
29	Labour and Employment	(Revenue)	1,60,936		1,60,930
30	Housing	(Revenue)	10,57,823		10,57,823
32	Other Administrative Services	(Capital)	38,32,553		38,32,553
33	Finance	(Revenue) (Capital)	1,36,21,257	9,57,46,834	1,36,21,257 9,57,46,834
35	Tribal Development	(Revenue)	1,17,61,898	_	1,17,61,898
	Total		23,35,76,480	9,57,46,834	32,93,23,314

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Clause (1) of Article 204 read with clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 1984-85.

VIRBHADRA SINGH, Chief Minister.

SHIMLA: The 3rd April, 1987.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(2) 1/86-II]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 1987, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill by the Legislative Assembly.